

FORM A**PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

**FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF
M/S ORIOR DEVELOPERS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED**

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	M/s Orior Developers and Infrastructure Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	27/06/2006
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies National Capital Territory of Delhi & Haryana
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70109DL2006PTC150338
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	<i>Registered Office:</i> Flat No.969 Radhika Apartment Sector-14, Pocket-1, Dwarka South West Delhi New Delhi - 110078 <i>Residential Township Project:</i> Bhaskar Enclave - II, Tonk Road, NH-12, Jaipur Rajasthan 302015
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	28.01.2022 (Order passed by Hon'ble Adjudicating Authority-National Company Law Tribunal New Delhi Bench V in Company Petition No. CP (IB) No.1529(ND) /2019 received on 31.01.2022)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	27 th July 2022
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name: Prabhakar Kumar Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00774/2018-2019/12373
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: E-18, Ground Floor, Guru Nanak Pura, Janakpuri, New Delhi, 110058 Email: prabhakar_acs@rediffmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: E-18, Ground Floor, Guru Nanak Pura, Janakpuri, New Delhi, 110058 Email: cirp.orior@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	14 February 2022 (Order received on 31 January 2022 from Hon'ble Adjudicating Authority, hence 14 days calculated from the receipt of order)
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim	The class of Creditors could not be ascertained at this stage. As the financial statement of Corporate Debtor are finalized and filed with the Registrar of



	resolution professional	Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana for the Financial Year 2014-15. Therefore, presently one class of creditors i.e. Allottees/ Investors under the Real Estate Project is being considered.
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. Anshuman Kaushik IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P-02523/2021-2022/13825 Email: anshumansk@gmail.com 2. Mr. Vinay Kumar Singhal IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00624/2018-2019/11880 Email: vinaysinghal.ip@gmail.com 3. Mr. Deepak Kumar Garg IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00796/2019 - 2020/12560 Email: deepakgarg07@rediffmail.com
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a) Relevant forms are available at https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details are available at: E-18, Ground Floor, Guru Nanak Pura, Janakpuri, New Delhi, 110058

Notice is hereby given that the Hon'ble Adjudicating Authority - National Company Law Tribunal, New Delhi Bench V has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of **M/s Orior Developers and Infrastructure Private Limited** on 28.01.2022 (Order received on 31.01.2022).

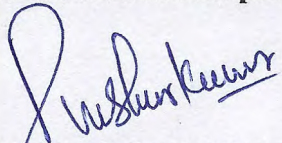
The creditors of **M/s Orior Developers and Infrastructure Private Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 14 February, 2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class Allottees/ Investors under the Real Estate Project in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of
Interim Resolution Professional


: PRABHAKAR KUMAR
IBBI/IPA-002/IP-N00774/2018-2019/12373



Date: 02.02.2022
Place: New Delhi

केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस के लिए खुला खजाना, जमीन-जायदाद क्षेत्र को हाथ लगी मायूसी

287 करोड़ रुपए से सीसीटीवी सीधे नहीं, परोक्ष रूप से थोड़ी की जद में होगी राजधानी राहत की उम्मीद

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 1 फरवरी। दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए इस बार के बजट में 1,701 करोड़ रुपए पिछले साल के मुकाबले ज्यादा मिले हैं। दिल्ली पुलिस को वर्ष 2021-22 के बजट में जहां 8654.26 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था। वहीं मंगलवार को पेश किए गए बजट में वर्ष 2022-23 के लिए 10355.29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि इस रकम से दिल्ली पुलिस खुद को अत्याधुनिक और सशक्त बनाएगी। साथ ही तकनीकी तौर पर अपने कार्यशैली को और मजबूत करेगी, जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली भर में सीसीटीवी लगाने के लिए 287 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

इन पर जोर
साइबर हाइवे, डिजिटल ट्रैकिंग रेडियो सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पुलिस के दफ्तर, भवन, आवासीय भवन, नए पुलिस मुख्यालय के रखरखाव का काम, दिल्ली पुलिस के लिए नए घर बनाने पर भी राशि खर्च होगी।
से संबंधित खर्च के लिए दिल्ली पुलिस को 9,808 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं 287 करोड़ रुपए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट में दिए गए हैं। साथ ही अन्य सुरक्षा उपकरण भी खरीदे जाएंगे। साथ ही 259 करोड़ रुपए पुलिस ढांचे के तौर पर मजबूत बनाने के लिए दिए गए हैं।

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 1 फरवरी। कोरोना महामारी के असर से देश का दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला रियल एस्टेट यानी जमीन-जायदाद से जुड़ा सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लिहाजा यह सेक्टर 2022-23 के केंद्रीय बजट से राहत की उम्मीद लगाए हुए था।
उत्तर भारत के रियल एस्टेट और फ्लैट कारोबार के प्रमुख केंद्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों ने बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48 हजार करोड़ रुपए के आबंटन से आवास ऋण में तेजी की उम्मीद है। निर्माण परियोजनाओं को उद्योग की तर्ज पर दर्जा और कर प्रोत्साहन में नाउम्मीदी रही है। क्रेडाई पश्चिम यूपी के अध्यक्ष और निदेशक एबीए कार्प अमित मोदी ने कहा कि बजट में कुछ टोस घोषणा जैसे उद्योग का दर्जा और डेवलपर्स के लिए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। हालांकि 2022-

23 में पीएम आवास योजना और 80 लाख घरों की किफायती आवास योजना के लिए 48, 000 करोड़ रुपए का आबंटन स्वागत योग्य है।
मास्टर्स इंफ्रा के निदेशक गुरुचरण सिंह ने कहा कि बजट में शहरी क्षमता के विकास, निर्माण, योजना कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा गठित योजनाकारों और अर्थशास्त्रियों की उच्च स्तरीय समिति की स्थापना आधुनिक शहरी योजना में एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि एकल खिड़की मंजूरी, इंफ्रा को उद्योग का दर्जा और अपेक्षित कर प्रोत्साहन में निराशा हाथ लगी है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए बजट मिला जुला रहा। सिक्का समूह के प्रबंध निदेशक हरविंदर सिंह ने कहा कि बजट से रियल एस्टेट क्षेत्र को सीधे तौर पर फायदा नहीं मिला लेकिन जो प्रावधान सरकार की तरफ से किए गए हैं, उनका फायदा इस सेक्टर को होगा। बेहतर आधारभूत ढांचा (कनेक्टिविटी) और प्रधानमंत्री आवास योजना राशि का आबंटन रोजगार के नए अवसरों को भी पैदा करेगा।

बजट पर किसने क्या कहा
बजट ने लोगों को मायूस किया है क्योंकि इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी। महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है। महामारी से प्रभावित आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई।
- अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
उद्योगपतियों को टैक्स में छूट, जनता को नहीं। किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं। पहले 2 करोड़ नौकरी का अब 60 लाख नौकरी का झांसा। वंदेभारत के नाम पर 400 ट्रेन पूंजीपतियों को देकर 'धन्यभारत' की शुरुआत कर दी केंद्र सरकार ने।
- संजय सिंह, राज्यसभा सदस्य
बजट में हर तबके का और खासतौर पर गरीब वर्ग पर खास ध्यान दिया गया है। 80 लाख नए घर बनाने की घोषणा से गरीबों का अपने घर का सपना साकार होगा। 25 हजार किमी लंबे राजमार्ग देश की तरकी को का नया अध्याय लिखने वाले हैं। बजट में विद्युत सामान, मोबाइल चार्जर, कैमरा, बटन, चमड़ा कई चीजें सस्ती होने वाली हैं।
- रामवीर सिंह बिधुड़ी, नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधानसभा
बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह सर्व समावेशी व कल्याणकारी बजट नए भारत के आकांक्षाओं को प्राप्त करने में मजबूती प्रदान करेगा। यह आने वाले समय में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा।
- आदेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा
बजट दिल्लीवासियों के लिए शून्य है। आसमान छूती महंगाई और कोरोना के कारण आर्थिक मंदी झेल रही राजधानी के लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। पेट्रोल-डीजल सहित रसोई गैस की बढ़ती दरों में कमी नहीं की गई। बजट में पूंजी पति मित्रों के हित साधने का काम किया है, जबकि गरीबों और नौकरीपेशा लोगों को दूर रखा।
- चौधरी अनिल कुमार, अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस
केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। किसानों को सरकार से सबसिडी में बढ़ोतरी, और ख्याज मुक्त ऋण नहीं दिया गया है। स्वामीनाथन समिति का बजट में कोई जिक्र नहीं होने से किसानों में निराशा है।
- नरेश कुमार, वरिष्ठ प्रवक्ता, दिल्ली कांग्रेस

किसानों को लगाई चपत : सिसोदिया
नई दिल्ली, 1 फरवरी (जसं)। दिल्ली सरकार में वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को चपत लगाई है। केंद्र का दावा झूठा है। प्रेस कांग्रेस में उन्होंने कहा-न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आबंटित धन में कमी, फसल खरीदारी के लक्ष्य में कमी, कृषि में नए आबंटन में कमी से किसानों का नुकसान हुआ है।

दि फेडरल बैंक लि. फेडरल बैंक
3/29, ईस्ट पटल नगर, नई दिल्ली-110008
पंजी-कार्यालय: अन्वयार्थ, केरल
सोने की गिञ्जी सिक्की के लिए सूचना
सभी सम्बंधितों की जानकारी हेतु एनएचआर सूचना वी जर्नी ई कि बैंक की मूबे बॉर्निंग जारुअ में स्पष्ट ऋण खातों में निम्नलिखित स्थान आवृत्त करवाये गये हैं, जो पुराने के लिए अतिरिक्त हो चुके हैं और नए-नए सूचना देने पर विचारित नहीं किए गए हैं, अतः निम्नलिखित स्थाने अनुसर 37.02.2022 को या उसके उपरान्त शाखा द्वारा किसी हेतु रबे जायेंगे:
शाखा / स्थान क्र.सं. नाम और खाना संख्या
3/29, ईस्ट पटल नगर, नई दिल्ली-110008 (1) नीधु चन्द्रन - 1845640006700
पत्ता: नई दिल्ली दिनांक: 02.02.2022 शाखा प्रबंधक, (दि फेडरल बैंक लि.)

प्रारंभिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अधिनियम 2016 के विनियमों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
मैसर्स ओरियर डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

क्र.सं.	नाम और खाना संख्या
1.	कोरपोरेट ऋणी का नाम
2.	कोरपोरेट ऋणी के निगमन की तिथि
3.	वह प्राधिकार जिसके अधीन कोरपोरेट ऋणी निर्माणित/रजिस्ट्रीकृत है
4.	कोरपोरेट प्राधान संख्या / कोरपोरेट ऋणी की सीमित दायित्व प्राधान संख्या
5.	कोरपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तथा प्राधान कार्यालय (पदि कोई है) का पता
6.	कोरपोरेट ऋणी की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने की प्राकल्पित तारीख
8.	अंतरिम समाधान व्यवसायिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यवसायिक का नाम व रजिस्ट्रीकरण संख्या
9.	अंतरिम समाधान व्यवसायिक का बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ईमेल
10.	अंतरिम समाधान व्यवसायिक के साथ पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और ई-मेल
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
12.	अंतरिम समाधान व्यवसायिक द्वारा अनिश्चित धारा 21 की उपधारा (क) की खंड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग, यदि कोई है
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के लिए अनिश्चित दिवाला व्यवसायिकों के नाम
14.	(क) सुसंगत प्रारूप और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे यहाँ उपलब्ध है

यह सूचना दी जाती है कि माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण - राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बैंक V ने मैसर्स ओरियर डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की कोरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 28.01.2022 को प्रारंभ करने का आदेश दिया है (आदेश 31.01.2022 को प्राप्त हुआ है)।
मैसर्स ओरियर डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से अंतरिम समाधान व्यवसायिक को प्रतिष्ठि सं. 10 के सामने उरिलिखित पते पर 14 फरवरी, 2022 को या उसके पूर्व संसूत सहित अपने दावे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।
वित्तीय लेनदार संसूत सहित अपने दावे केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार संसूत सहित अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रतिष्ठि सं. 12 के सामने सूचीबद्ध किसी वर्ग का कोई वित्तीय लेनदार प्रतिष्ठि सं. 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवाला व्यवसायिकों में से कम से कम एक के रूप में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत आवंटित/निवेशकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसन्दप्ररूपक में उपदर्शित करेगा।
दावे के झूठे या धामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लग सकता है।
अंतरिम समाधान व्यवसायिक का नाम और हस्ताक्षर: प्रभाकर कुमार, प्रभाकर कुमार
दिनांक: 02.02.2022
स्थान: नई दिल्ली
IBBI/PA-002/IP-N00774/2018-2019/12373

राष्ट्रीय समारोह

समय: प्रातः 9:00 बजे स्थान: सुल्तानपुर नेशनल पार्क, गुरुग्राम

- | | |
|--|--|
| अध्यक्षता
श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा | मुख्य अतिथि
श्री भूपेन्द्र यादव
केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन |
| विशिष्ट अतिथि
श्री अश्विनी कुमार चौबे
केन्द्रीय राज्य मंत्री, पर्यावरण एवं वन | श्री कंवर पाल
वन एवं पर्यटन मंत्री, हरियाणा |



वन एवं वन्य जीव विभाग, हरियाणा
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा

कार्यक्रम से जुड़ने के लिए
व्हाट्सएप कोड स्कैन करें

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा | www.prharyana.gov.in | @DiprHaryana



Eastern Coalfields Limited
(A Subsidiary of Coal India Limited)



NOTICE

"All the tenders issued by CIL and its subsidiaries for procurement of Goods, Works & Services are available on (i) Website of Coal India Limited : www.coalindia.in, (ii) Website of ECL : www.easterncoal.nic.in, (iii) CIL e-Procurement Portal : <https://coalindiatenders.nic.in>, (iv) Central Public Procurement Portal : <https://eprocure.gov.in> In addition, procurement is also done through GeM Portal : <https://gem.gov.in>".

(By Order), ECL

VISIT US AT : www.easterncoal.nic.in

**Book your
Classified Ad in
3 easy steps**



Scan QR code
or logon to

ads.timesgroup.com

1. Select your city and ad type
2. Upload your creatives and content
3. Pay online

Exclusive offers | 100% online

TIMES interact
Connecting People, Connecting Needs.

To book your ad

Logon to: ads.timesgroup.com
or Call: 18001205474 (Toll Free)



KERALA WATER AUTHORITY - e-TENDER NOTICE

Tender No : Re T No.71/2021-22/SE/Q - KILFB-Augmentation of WSS to Kollam - Phase II Package V-Part I(a), I(b), II, III, IV & V - Electrical and Mechanical components- Supply, erection and commissioning of pumpsets, Providing electrical substations and allied works, providing Automation System (SCADA), installation of CCTV, Solar PV system etc. at WTP and Raw water pump house at Vasoorchira and Njankadavu. • EMD : Rs. 500000 • Tender fee : Rs. 15000+2700 (18% GST-It will be paid by the contractor on reverse charge basis while filing his returns) • Last Date for submitting Tender : 21-02-2022, 02:00:pm • Phone : 0474 27454293 • Website : www.kwa.kerala.gov.in | www.etenders.kerala.gov.in
KWA-JB-GL-6-987-2021-22
Superintending Engineer, PH Circle, Kollam

KUDUMBASHREE NATIONAL RESOURCE ORGANISATION

3rd Floor, Carmel Towers, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram 695014

Invites Proposals for

Documentation of Start-Up Village Entrepreneurship Programme (SVEP) Phase II blocks and Experiences of Mentor Resource Persons in Enterprise Domain in all/either of the three regions:

(i) Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh, (ii) Kerala, (iii) Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana.

Last date for submission of bid: 14/02/2022, To download the notification & application form, please visit <https://etenders.kerala.gov.in/nicgep/app>

(Tender Ids: 2022_SPEM_470994_1, 2022_SPEM_471097_1, 2022_SPEM_471087_1). Last date for downloading form: 12th February 2022.

To know more, visit: <https://www.kudumbashreenro.org/>

**FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S ORIOR DEVELOPERS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	M/s Orior Developers and Infrastructure Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	27/06/2006
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated /registered	Registrar of Companies National Capital Territory of Delhi & Haryana
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70109DL2006PTC150338
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: Flat No.969, Radhika Apartment, Sector-14, Pocket-1, Dwarka South West Delhi, New Delhi-110078 Residential Township Project: Bhaskar Enclave-II, Tonk Road, NH-12, Jaipur Rajasthan- 302015
6.	Insolvency commencement date respect of corporate debtor	28.01.2022 (Order passed by Hon'ble Adjudicating Authority-National Company Law Tribunal New Delhi Bench V in Company Petition No. CP (IB) No.1529 (ND)/2019 received on 31.01.2022)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	27 th July 2022
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Name: Prabhakar Kumar Reg. No.: IBBI/PA-002/IP-N00774/2018-2019/12373
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: E-18, Ground Floor, Guru Nanak Pura, Janakpuri, New Delhi, 110058 Email: prabhakar_acs@rediffmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional,	Address: E-18, Ground Floor, Guru Nanak Pura, Janakpuri, New Delhi, 110058 Email: cirp.orior@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	14 February 2022 (Order received on 31 January 2022 from Hon'ble Adjudicating Authority, hence 14 days calculated from the receipt of order)
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	The class of Creditors could not be ascertained at this stage. As the financial statement of Corporate Debtor are finalized and filed with the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana for the Financial Year 2014-15. Therefore, presently one class of creditors i.e. Allottees/ Investors under the Real Estate Project is being considered.
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1.Anshuman Kaushik, IBBI Reg. No: IBBI/PA-001/IP-P-02523/2021-2022/13825 Email: anshumanksk@gmail.com 2.Mr. Vinay Kumar Singhal, IBBI Reg. No.: IBBI/PA-002/IP-N00624/2018-2019/11880 Email: vinaysinghal.ip@gmail.com 3.Mr. Deepak Kumar Garg, IBBI Reg. No.: IBBI/PA-002/IP-N00796/2019 -2020/12560 Email: deepakgarg07@rediffmail.com
14.	(a) Relevant Forms and (b)Details of authorized representatives are available at:	(a) Relevant forms are available at https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details are available at: E-18, Ground Floor, Guru Nanak Pura, Janakpuri, New Delhi, 110058

Notice is hereby given that the Hon'ble Adjudicating Authority - National Company Law Tribunal, New Delhi Bench V has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of **M/s Orior Developers and Infrastructure Private Limited** on 28.01.2022 (Order received on 31.01.2022).

The creditors of **M/s Orior Developers and Infrastructure Private Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 14 February, 2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class Allottees/ Investors under the Real Estate Project in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional:
Sd./

Date: 02.02.2022
Place: New Delhi

PRABHAKAR KUMAR
IBBI/PA-002/IP-N00774/2018-2019/12373

TimesP
and cura

C
authentic



f TimesP

MO

L

